



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 486 ] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 22, 1995/अग्रहायण 1, 1917  
No. 486] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 1995/AGRAHAYANA 1, 1917

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

विदेश कर प्रभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1995

आय-कर

सा. क. नि. 761 अ.—चूंकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपव्ययन के परिहार के लिए भारत गणराज्य की सरकार और माल्टा की गणराज्य सरकार के बीच सम्पन्न सलग्न करार, उक्त करार के अनुच्छेद 29 के पैरा 1 के अनुसार उक्त करार को लागू करने के लिए दोनों ही सीवदाकारी राज्यों द्वारा अपने-अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में एक दूसरे के लिए अधिसूचना जारी करने के पश्चात्, 8 फरवरी, 1995 से प्रवृत्त हो गया है।

अतः अब आयकर अधिनियम, 1961 §1961 का 43 की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्वेश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंध भारत संधि में लागू किये जाएंगे।

"अनुसूची"

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और  
राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य

और

माल्टा

के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार

और

माल्टा की सरकार

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए  
एक करार सम्पन्न करने की इच्छा से;

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

## अध्याय I

## करार का विषय-क्षेत्र

## अनुच्छेद - 1

## वैयक्तिक क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो सौविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं ।

## अनुच्छेद - 2

## करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा वे इस प्रकार हैं :-

§क§ भारत में :

आयकर, जिसमें उस पर लगने वाला कोई आधेभार भी शामिल है;

§जिन्हें इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा§

§ख§ माल्टा में :

आयकर;

§जिन्हें इसके बाद "माल्टा कर" कहा जाएगा§ ।

2. यह करार किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के करों पर भी लागू होगा, जो दोनों सौविदाकारी राज्यों द्वारा मौजूदा करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् पैराग्राफ §i§ में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । सौविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारी अपने-अपने क़राधान क़ानूनों में किए गए किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को सूचित करेंगे ।

3. इस अनुच्छेद के अन्य उपबंधों के होते हुए भी, यह करार माल्टा में उत्पादित पेट्रोलियम के उत्पादन में लगे किसी व्यक्ति की कर-प्रमाय आय से संबंधित, आयकर अधिनियम की धारा 31 की उपधारा §ii§ §अध्याय 123§ अथवा इस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख के पश्चात् लागू किया गया सारतः इसी प्रकार के किसी उपबंध के अंतर्गत माल्टा में दिया गया अथवा देय-कर पर लागू नहीं होगा ।

## अध्याय II

## परिभाषाएं

## अनुच्छेद - 3

## सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :

§क§ "भारत" पद से अभिप्रेत है- भारत का राज्य क्षेत्र तथा उसमें शामिल राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर का वायुमण्डलीय क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिस पर भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों/समुद्र क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र संघ के कानूनों के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता-सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हो;

§ख§ "माल्टा" पद से अभिप्रेत है जब वह भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है तो इसका अर्थ है - माल्टा के द्वीप, गोर्जो के द्वीप और माल्टा - वायु-मंडल के अन्य द्वीप जिनमें इनके जल क्षेत्र, तथा माल्टा समुद्र क्षेत्र के परे का कोई ऐसा क्षेत्र भी शामिल है, जिसे अन्तरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत, महाद्वीपीय कगार से संबंधित माल्टा के कानून के तहत, ऐसे क्षेत्र के रूप में नामोद्घट्ट कर दिया गया हो अथवा इसके बाद नामोद्घट्ट कर दिया जाए, जिस पर समुद्र क्षेत्र और उप-भूखण्ड और उनके प्राकृतिक संसाधनों पर माल्टा के अधिकार हों;

§ग§ "कम्पनी" पद से कोई भी ऐसा निर्गमित निकाय अथवा कोई भी सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निर्गमित निकाय के रूप में माना जाता है;

§घ§ "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है - भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय §राजस्व विभाग§ अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि और माल्टा के मामले में, माल्टा का वित्त मंत्री अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

§ङ.§ "सौविदाकारी राज्य" तथा "दूसरे सौविदाकारी राज्य" पदों से, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा माल्टा अभिप्रेत है;

§च§ "एक सौविदाकारी राज्य का उद्यम" और दूसरे सौविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम और दूसरे सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

§छ§ भारतीय कर से संबंधित "वित्तीय वर्ष" पद से अभिप्रेत है - "पूर्ववर्ती वर्ष" जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 §1961 का 43§ में परिभाषित है और माल्टा कर से अभिप्रेत है - "कर निर्धारण वर्ष" का तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष जैसा कि आयकर अधिनियम §केप 123§ में परिभाषित है;

- § ज § "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है - किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक सौविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे सौविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;
- § झ § "राष्ट्रक" पद से अभिप्रेत है - किसी सौविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता प्राप्त कोई व्यापक और कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था जिसे अपनी यह हैसियत उस सौविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों के अनुसार प्राप्त हुई हो;
- § ञ § "व्यक्ति" पद में कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, व्यक्तियों की कोई संस्था और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित सौविदाकारी राज्यों में लागू करायान कानूनों के अंतर्गत कराधेय एक के रूप में माना जाता है;
- § ट § "कर" पद से अभिप्रेत है - भारतीय कर अथवा माल्ट कर, जैसी कि विषयगत पाठ में अपेक्षा की गयी हो, लेकिन इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी चुक अथवा भूल के संबंध में देय है जिसके लिए यह करार लागू होता है अथवा उन करों के संबंध में लगाया गया कोई आर्थिक दण्ड निरूपित करता है ।

2. जहां तक किसी सौविदाकारी राज्य द्वारा इस करार के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्द का जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो, जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अथवा होगा जो उस सौविदाकारी राज्य के करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जो इस करार के विषय हैं ।

#### अनुच्छेद - 4

##### निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, "किसी सौविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है - कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर, उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत, उसके अधिवास, निवास, प्रबंध-स्थान अथवा इस प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण, वहां कर लगाया जा सकता है ।

2. जहां पैराग्राफ § 1 § के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों सौविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

- § क § उसे उस सौविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों सौविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी-गृह उपलब्ध हो तो

वह उस सौविदाकारी राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हों §महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र§;

§ख§ यदि उस सौविदाकारी राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र हो अथवा यदि उसका दोनों सौविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी-गृह नहीं हो, तो वह उस सौविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो;

§ग§ यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस सौविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रक है;

§घ§ यदि वह दोनों राज्यों का राष्ट्रक है अथवा दोनों में से किसी का भी राष्ट्रक नहीं है तो सौविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारी इस प्रश्न को आपसी सहमति से हल करेंगे ।

3. जहां पैरा §1§ के उपबंधों के आधार पर व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों सौविदाकारी राज्यों का निवासी है वहां यह समझा जाएगा कि वह उस सौविदाकारी राज्य का राष्ट्रक है जिसमें उसके प्रभावी प्रबंध का स्थान स्थित है ।

### अनुच्छेद - 5

#### स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "स्थायी संस्थापन" शब्दावली का अर्थ कारोबार का वह नियत स्थान है जिसके माध्यम से उद्यम का कारोबार पूर्णतः अथवा अंशतः संचालित होता है ।

2. "स्थायी संस्थापन" शब्दावली के अंतर्गत विशेषतः निम्नलिखित शामिल हैं :

§क§ प्रबंध का कोई स्थान;

§ख§ कोई शाखा;

§ग§ कोई कार्यालय;

§घ§ कोई कारखाना;

§ड. § कोई कार्यशाला;

§च§ कोई खान, कोई तेल अथवा गैस कूप, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान जिसमें अप्टट ड्रिलिंग स्थल भी शामिल है;

§छ§ भवन, स्थल अथवा निर्माण अथवा संयोजन परियोजना अथवा उनके संबंध में पर्यवेक्षा क्रियाकलाप जहां ऐसा स्थल, परियोजना अथवा क्रियाकलाप §अन्य ऐसे स्थलों,

परियोजना और क्रियाकलापों, यदि कोई हों, के साथ छः माह की अवधि से अधिक समय तक जारी रहें;

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

- ॥क॥ किसी उद्यम के माल अथवा फण्य-वस्तुओं के केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग;
- ॥ख॥ केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा फण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखना;
- ॥ग॥ किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा फण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखना;
- ॥घ॥ किसी उद्यम के लिए माल अथवा फण्य-वस्तुओं का केवल क्य करने अथवा सूचना फ़र्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;
- ॥ङ॥ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना जो केवल उद्यम के कारोबार को चलाने के लिए अथवा अन्य किसी ऐसे कार्यकलाप के लिए हो जो प्रारंभिक अथवा सहायक क्रिम का हो ।

4. सौविदाकारी राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी सौविदाकारी राज्य में समुद्र में तेल और इसकी अवमृदा की खोज करने अथवा वहां स्थित प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने, अथवा इस प्रकार की गतिविधियों में लगा हुआ हो, जो ऐसी गतिविधियों की पूरक अथवा सहायक हों तो उस व्यक्ति की ऐसी गतिविधियां उस राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन के माध्यम से मानी जाएंगी ।

5. एक सौविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे सौविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन तभी माना जाएगा यदि :

- ॥क॥ उद्यम द्वारा उसके लिए अथवा उसके साथ सौविदा के अंतर्गत उस राज्य में महत्वपूर्ण उपस्कर प्रयोग या प्रतिष्ठापित किए जा रहे हों;
- ॥ख॥ यह उप-पैराग्राफ ॥क॥ में उल्लिखित उपस्कर के प्रयोग के संबंध में उस राज्य में पर्यवेक्षी कार्यकलाप करता हो ।

6. पैराग्राफ ॥1॥ और ॥2॥ के उपबंधों के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति - स्वतंत्र नैसयत के किसी एजेंट से भिन्न जिस पर पैराग्राफ ॥7॥ लागू होता है - किसी उद्यम की ओर से कार्य करता है और वह किसी सौविदाकारी राज्य में उद्यम के नाम पर आदतन सौविदा संपन्न करने के प्राधिकार का प्रयोग करता है, तब उस उद्यम का ऐसी गतिविधियों के संबंध में उस राज्य में स्थायी संस्थापन माना जाएगा जो वह

व्यक्ति उद्यम के लिए करता है बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां उद्यम के लिए माल अथवा फ्य-वस्तुओं की खरीद तक ही सीमित न हों ।

7. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी-संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, जहां ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में कार्य करते हों ।

लेकिन जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किये जाते हैं, तो उसे स्वतंत्र हैसियत वाला एजेंट नहीं समझा जाएगा, यदि एजेंट और उद्यम के बीच सीदे निष्पक्ष-शर्तों के तहत नहीं किए गए हों ।

8. यदि कोई कंपनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी कंपनी द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य में §चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा§ कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी कंपनी को स्वतः ही दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

### अध्याय III

#### आय पर करधान

#### अनुच्छेद - 6

#### अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति §कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय भी शामिल है§ से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. "अचल संपत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है, जिसमें सम्बन्धित संपत्ति स्थित है । पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे - अचल संपत्ति के अयसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल संपत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भंडार स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्राप्तफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार । जलयान, नौकाएं तथा विमान अचल संपत्ति नहीं माने जाएंगे ।



3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग से किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे ।

4. पैराग्राफ §1§ और §3§ के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर, और स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे।

### अनुच्छेद - 7

#### कारोबार से लाभ

1. एक सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि यह उद्यम दूसरे सविदाकारी राज्य में वहां स्थित स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं करता हो । यदि उक्त उद्यम पूर्वोक्त प्रकार से कारोबार कर रहा हो, तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लग सकता है परन्तु केवल लाभों के उतने अंश पर ही कर, प्रत्यक्षः अथवा अप्रत्यक्षतः लगाया जा सकेगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारण हुआ हो ।

इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष" शब्दों का अर्थ है कि जहां कोई स्थायी संस्थापन उद्यम द्वारा किए गए करारों पर बातचीत करने, इन्हें सम्पन्न करने अथवा इन्हें पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेता है, तब इस बात के होते हुए भी कि उद्यम के अन्य भागों ने भी इन कार्य सम्पन्ननों में हिस्सा लिया है, तब उन करारों से उत्पन्न होने वाले उद्यम के लाभों के अनुषंग में जिनमें उद्यम के ऐसे लेन-देन के कारण उत्पन्न हुए समग्र लाभों में स्थायी संस्थापन का अंशदान माना जाएगा ।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक सविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के जरिए कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक सविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा जो उसको प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक-समान अथवा उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता, जिसका एक स्थायी संस्थापन है अथवा अन्य सम्बद्ध उद्यम जिनके साथ यह लेन-देन करता है ।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में, उद्यम के खर्चों की कटौतियों § इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्ययों सहित § के रूप में अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं और जो कटौती दिए जाने योग्य होंगे यदि वह स्थायी संस्थापन

एक ऐसी स्वतंत्र सत्ता होती जिसने उस राज्य के कराधान कानूनों के उपबंधों तथा इसकी सीमाओं के अनुसार ये खर्चे किए हों, चाहे ये उस सौविदाकारी राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा अन्यत्र ।

4. इस अनुच्छेद में कुछ भी, किसी व्यक्ति की कर-देयता का निर्धारण करने संबंधी उस सौविदाकारी राज्य के किसी कानून को लागू करने से प्रभावित नहीं करेगा, इसमें विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसी देयता का निर्धारण करना अथवा उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना से सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे मामलों में आकलन करना भी शामिल है जहां किसी स्थायी संस्थापन के कारण समझे जाने वाले लाभों को सुनिश्चित कर पाना संभव अथवा व्यवहार्य न हो बशर्ते कि उस कानून को लागू किया जाएगा जहां तक सक्षम प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना इस अनुच्छेद के सिद्धांतों के अनुसार अनुमति दे ।

5. कोई लाभ, केवल इस कारण किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा फण्य-वस्तुएं खरीदी गई हैं ।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हो ।

7. इस अनुच्छेद के उपबंधों से, किसी सौविदाकारी राज्य के बीमे संबंधी कारोबार से हुए लाभों के कराधान संबंधी कानून के उपबंध प्रभावित नहीं होंगे ।

8. जहां लाभों में आय की वे मदें शामिल हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

### अनुच्छेद - 8

#### जहाजगानी तथा वायुपरिवहन

1. किसी सौविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में उस उद्यम के जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से प्राप्त लाभ का अर्थ है - पैराग्राफ 1 में वर्णित किसी उद्यम द्वारा जलयानों अथवा वायुयानों के मालिकों या पट्टेदारों अथवा चार्टरों द्वारा क्रमशः जलयान अथवा वायुयान द्वारा यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा माल के परिवहन से प्राप्त लाभ जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

{क} अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री ;

§ख§ ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित अन्य कार्यकलाप;

§ग§ जलयानों अथवा वायुयान को किराए पर देना जो ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित किसी कार्यकलाप के लिए आनुषंगिक हैं ।

3. पैराग्राफ §1§ में वर्णित किसी सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन के संबंध में प्रयुक्त कंटेनरों के §जिनमें कंटेनरों के परिवहन के लिए ट्रैलर, बर्गेज तथा तत्संबंधी साज-सामान भी शामिल हैं। इस्तेमाल, रखरखाव अथवा किराये से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।

4. पैराग्राफ §1§ तथा §3§ के उपबंध किसी फ्ल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेन्सी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से संबंधित निधियों के ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभों के रूप में माना जाएगा, तथा अनुच्छेद 11 §ब्याज§ के उपबंध ऐसे ब्याज के मामले में लागू नहीं होंगे ।

#### अनुच्छेद - 9

#### सहयोगी उद्यम

जहां:

§क§ एक सविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा

§ख§ वे ही व्यक्ति, एक सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न है, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण, उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा ।

2. इस अनुच्छेद के होते हुए भी, ऐसे मामलों में जहां किसी उद्यम को हुई समझी जाने वाली आय का निर्धारण करना संभव नहीं है अथवा व्यवहार्य नहीं है वहां पर उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी

के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करके अथवा उपलब्ध सूचना के आधार पर उस राज्य के सक्षम अधिकारी के द्वारा अनुमान लगाकर ऐसी देयता निर्धारित करने के संबंध में किसी संविदाकारी राज्य के किसी कानून के लागू होने के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि जहां तक सक्षम अधिकारी को उपलब्ध सूचना इस अनुच्छेद के सिद्धांतों के अनुरूप अनुमति देती हो उस सीमा तक वह कानून लागू किया जाए।

3. जहां तक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है - जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार के लाभों को सम्मिलित करता है जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें इस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होतीं, तब दूसरा राज्य उन लाभों पर वहां प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में, इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारी एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

### अनुच्छेद - 10

#### लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किये गये लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी, उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु :

§क§ जहां भारतीय निवासी कम्पनी द्वारा मरुटा के निवासी को लाभांश अदा किया जाता है जो उसका वहां हिताधिकारी-स्वामी है, तो इस प्रकार प्रभारित भारतीय कर इससे अधिक नहीं होगा :

§ii§ यदि हिताधिकारी-स्वामी ऐसी कम्पनी है जिसके पास लाभांश अदा करने वाली कम्पनी के कम से कम 25 प्रतिशत शेयर हों तो लाभांश की सकल रकम का 10 प्रतिशत; और

§iii§ अन्य सभी मामलों में लाभांश की सकल रकम का 15 प्रतिशत।

§ख§ जहां किसी ऐसी कम्पनी द्वारा लाभांश अदा किया जाता है जो मरुटा की निवासी है और भारतीय निवासी को लाभांश अदा करती है जो उसका वहां हिताधिकारी-स्वामी है तो

माल्टा कर लभांश की सकल रकम से अधिक नहीं होगा जो उस लाभ पर प्रभार्य है जिस पर लभांश अदा किया जाता है । इस पैराग्राफ का उन लाभों के संबंध में कम्पनी के करधान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनमें से लभांशों का भुगतान किया जाता है ।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "लभांश" शब्द का अभिप्राय, शेयरों, "जेयोसेन्स" शेयर अथवा "जेयोसेन्स" राइट्स, खनन शेयरों, प्रवर्तक के शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है जो लाभ की भागीदारिता के ऋण-दाये नहीं हों और अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है, जिस पर वही करधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों के अन्तर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है ।

4. पैराग्राफ § 18 और § 28 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लभांशों का हिताधिकारी-स्वामी, जो एक सविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे सविदाकारी राज्य में कारोबार करता है जिसकी लभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है, वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से, अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लभांशों की अदायगी की जाती है, वहां वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है । ऐसे मामले में, यथास्थिति, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे ।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक सविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे सविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लभांशों पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, सिवाय उस स्थिति के जहां तक कि ऐसे लभांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किये जाते हों अथवा जहां तक कि जिस धारणाधिकार के बारे में लभांशों की अदायगी की जाती है, वह उस राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है, और न ही वहां उस दूसरे राज्य में कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ संबंधी कर नहीं लगाया जायेगा, चाहे अदा किये गये लभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों ।

### अनुच्छेद - 11

#### न्याज

1. एक सविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले तथा दूसरे सविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किये जाने वाले न्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जायेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार के न्याज पर उस सविदाकारी राज्य में तथा उस राज्य के कानूनों के

अनुसार कर लगाया जायेगा, जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हिताधिकारी-स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. पैराग्राफ § 2१ के उपबंधों के होते हुए भी, किसी सौविदाकारी राज्य में उद्भूत ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी यदि वह दूसरे सौविदाकारी राज्य की सरकार अथवा उसके किसी क्षेत्रीय प्राधिकरण अथवा किसी एजेन्सी द्वारा प्राप्त किया जाता है अथवा उस सरकार अथवा क्षेत्रीय प्राधिकरण के माध्यम से पूर्णतः उसके स्वामित्व तथा नियंत्रण में हो ।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "ब्याज" पद से अभिप्रेत है - प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं हों और चाहे उन्हें ऋण-दाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से, सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रिमियम और पुरस्कार शामिल हों ।

5. पैराग्राफ § 1१ और § 2१ के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हिताधिकारी-स्वामी सौविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे सौविदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता हो और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

6. ब्याज किसी सौविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जायेगा, जब ब्याज अदा करने वाली स्वयं वह सौविदाकारी राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो । किन्तु, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी सौविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, सौविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है, और इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है ।

7. जहां, ब्याज अदाकर्ता तथा हिताधिकारी-स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋण-दावे की ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए वह अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार

का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितधिकारी-स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, उस क्वॉटर के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करती हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जायेगा ।

### अनुच्छेद - 12

#### रायल्टियाँ और शामिल सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों और शामिल सेवाओं के लिए फीसों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियाँ और शामिल सेवाओं के लिए फीसों पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत होती हों, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायल्टियाँ अथवा शामिल सेवाओं के लिए फीसों का हितधिकारी-स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों अथवा शामिल सेवाओं के लिए फीसों की सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।
3. इस अनुच्छेद में "रायल्टियाँ" पद का अर्थ है - अदायगियाँ अथवा क्रेडिट, चाहे आवधिक हों अथवा नहीं हों और, तथापि जो उस सीमा तक वर्णित अथवा संगणित हों जहां तक ये अदायगियाँ निम्नलिखित के लिए प्रतिफल के रूप में की जाती हैं :

- १क॥ किसी कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान गुन फार्मूले अथवा प्रोसेस ट्रेडमार्क अथवा अन्य, जैसे सम्पत्ति अथवा अधिकार के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार;
- १ख॥ किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर का प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार;
- १ग॥ वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक जानकारी अथवा सूचना की आपूर्ति;
- १घ॥ निम्नलिखित का प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार;
  - १i॥ चलचित्र फिल्में;
  - १ii॥ दूरदर्शन के उपयोग के लिए फिल्में अथवा वीडियो टेपें; अथवा
  - १iii॥ रेडियो प्रसारण के संबंध में उपयोग के लिए टेपें; अथवा
- १ङ॥ इस पैराग्राफ में उल्लिखित अधिकार अथवा किसी सम्पत्ति की आपूर्ति अथवा उपयोग के संबंध में पूर्णतः अथवा आंशिक परिहार ।

4. इस अनुच्छेद में "शामिल सेवाओं के लिए फीसों" पद का अर्थ है - अदायगियाँ अथवा क्रेडिट, चाहे आवधिक हों अथवा नहीं हों, और तथापि जो उस सीमा तक वर्णित अथवा संगणित हों जहां तक ये अदायगियाँ निम्नलिखित के लिए प्रतिफल के रूप में की जाती हैं :

॥क॥ किसी ऐसी सहायता को प्रदान करना जो कि किसी ऐसी सम्पत्ति अथवा अधिकार के उपयोग अथवा भोगने के लिए अनुपंगी और सहायक है जैसा कि पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ ॥क॥ में उल्लेख किया गया है, ऐसा कोई उपस्कर जैसा कि पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ ॥ख॥ में उल्लिखित है अथवा ऐसी कोई जानकारी अथवा सूचना जैसा कि पैराग्राफ ॥3॥ के उप-पैराग्राफ ॥ग॥ में उल्लिखित है ।

॥ख॥ ऐसी तकनीकी अथवा परामर्शदात्री सेवायें ॥तकनीकी अथवा अन्य कार्मिक सेवाओं की व्यवस्था सहित॥ प्रदान करना यदि ऐसी सेवायें तकनीकी जानकारी, अनुभव, कौशल, जानकारी अथवा प्रक्रिया उपलब्ध कराती हों जिनमें तकनीकी प्लान अथवा तकनीकी डिजाइन का विकास अथवा अन्तरण शामिल है ।

5. पैराग्राफ ॥1॥ और ॥2॥ के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों और शामिल सेवाओं के लिए फीस का हितधिकारी-स्वामी, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने से, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियों अथवा शामिल सेवाओं के लिए फीस उत्पन्न हुई हों, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवायें करता है, तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियां तथा शामिल सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती हैं, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो, ऐसे मामले में, यथा-स्थिति, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे।

6. रायल्टियों और शामिल सेवाओं के लिए फीस किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई तभी मानी जायेगी, जब रायल्टियां और शामिल सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो, किंतु, जहां रायल्टियों अथवा शामिल सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियों अथवा शामिल सेवाओं के लिए फीस अदा करने का वचन दिया गया हो, तथा इस प्रकार की रायल्टियां अथवा शामिल सेवाओं के लिए फीस इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तो इस प्रकार की रायल्टियां उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जायेंगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

7. जहां अदाकर्ता और हितधिकारी-स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियों अथवा शामिल सेवाओं के लिए फीस की रकम,



इसके उपयोग, अधिकार तथा सूचना, जिसके लिए इसकी अदायगी की गई थी, उस रकम से बढ़ जाती है जिनकी रकम के बारे में इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता तथा हिताधिकारी-स्वामी के बीच सहमति हुई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम-वर्षित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदा की गई रकम के अतिरिक्त भाग पर, इस कथार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

### अनुच्छेद - 13

#### तकनीकी फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली तकनीकी फीस जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की जाती है उस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. तथापि, ऐसी तकनीकी फीस पर, उस संविदाकारी राज्य में भी जिसमें वह उद्भूत होती है, उसी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा। लेकिन, यदि प्राप्तकर्ता तकनीकी फीस का हिताधिकारी-स्वामी हो तो इस प्रकार से लगाया गया कर तकनीकी फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी फीस" पद, तकनीकी, प्रबंधकीय अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाओं के लिए, प्रतिफल के रूप में, अदायगियाँ करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी को दी जाने वाली अदायगियों से भिन्न, किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अदायगियों, से अभिप्रेत है।
4. पैराग्राफ § 1§ और § 2§ के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी फीसों का हिताधिकारी-स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें तकनीकी फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पन्न करता है और तकनीकी फीसों ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा ऐसी सेवाओं के साथ प्रभावी रूप से संबंधित हैं। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा 15 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।
5. एक संविदाकारी राज्य में तकनीकी फीस उद्भूत हुई तभी मानी जाएगी जब फीस अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-भाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उसका कोई सांविधिक निकाय अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां तकनीकी फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, एक संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन हो, जिसके संबंध में तकनीकी फीस अदा करने का वचन दिया गया हो, और ऐसी

तकनीकी फीस उस स्थायी संस्थापन द्वारा बढन की जाती हो तब ऐसी तकनीकी फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन स्थित है ।

6. जहां अदाकर्ता और प्राप्तकर्ता अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई तकनीकी फीस की रकम, किसी भी कारण से उस रकम से बढ़ जाती है जितनी रकम के बारे में इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हिताधिकारी-स्वामी के बीच सहमति हुई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । इस करार के अन्य उपबंधों पर यथोचित ध्यान देते हुए ऐसे मामले में अदायगियों का आधिक्य भाग प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय होगा ।

### अनुच्छेद - 14

#### संपत्ति का अंतरण

1. अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ §2§ में यथा-परिभाषित अचल संपत्ति के अन्तरण से होने वाले अभिलम्भों से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है ;

2. किसी कंपनी के शेयरों अथवा तुल्य हितों के अंतरण से होने वाले अभिलम्भों की आय पर, जिसकी परिसंपत्तियों में अचल संपत्ति पूर्ण रूप से अथवा मुख्य रूप से शामिल हैं, पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसमें कंपनी की परिसंपत्तियाँ अथवा मुख्य परिसंपत्तियाँ स्थित हैं ।

3. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलम्भों की आय पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारबार-संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलम्भों पर, जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन §अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ§ अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले लाभ अथवा आय भी शामिल है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

4. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल-संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलम्भों की आय पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसका अंतरणकर्ता निवासी है ।

5. किसी ऐसी कंपनी के, जो संविदाकारी राज्य की निवासी हो, पैराग्राफ §2§ में उल्लिखित शेयरों से भिन्न, शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलम्भों की आय पर, उसी राज्य में कर लगेगा ।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न, किसी भी संपत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलक्षणों की आय पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता निवासी है ।

### अनुच्छेद - 15

#### स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप के अन्य क्रियाकलापों के संबंध में प्राप्त आय पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा । तथापि, ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में निम्नलिखित परिस्थितियों में कर लगाया जा सकेगा :

§ क § यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है, अथवा

§ स § यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अवधियाँ किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 90 दिन अथवा उससे अधिक हों ।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में विशेष रूप से स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी क्रियाकलाप तथा चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं ।

### अनुच्छेद - 16

#### परकलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इस प्रकार के अन्य परिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, बशर्ते कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है । यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है तो जो परिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. पैराग्राफ § 1 § के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किये गये किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त परिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

॥क॥ प्राप्तकर्ता, संबंधित वित्तीय वर्ष में ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक नहीं है; और

॥ख॥ परिश्रमिक ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और

॥ग॥ परिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा किसी निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है जो नियोजक का दूसरे राज्य में है ।

3- इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन के संबंध में उन पर सवार हो कर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त परिश्रमिक पर कर उसी राज्य में ही लगाया जा सकेगा ।

#### अनुच्छेद - 17

##### निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी प्रकार की अन्य अदायगियों, जो किसी एक सविदाकारी राज्य की निवासी के द्वारा किसी कंपनी जो कि दूसरे सविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल अथवा "यथा-वर्धित" अन्य तुल्य निकाय के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हों, पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

#### अनुच्छेद - 18

##### कलाकारों और सिताड़ियों द्वारा वर्धित आय

1- अनुच्छेद 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी, एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्त्ता, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार अथवा किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे सविदाकारी राज्य में किए गए उस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्यक्रमों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2- जहां किसी मनोरंजनकर्त्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्यक्रमों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्त्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी, उस सविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यक्रमों किए जाते हैं ।

3- पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी मनोरंजनकर्त्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, जो एक सविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे सविदाकारी राज्य में उसी हैसियत से किए गए अपने वैयक्तिक

कार्यकलापों से अर्जित आय प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगी, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में कार्यकलाप प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की, जिसमें उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं, सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थित होते हों।

4. पैराग्राफ 2 तथा अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी मनोरंजनकर्त्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा उसी हेतुसयत से एक संविदाकारी राज्य में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय, मनोरंजनकर्त्ता अथवा स्वयं खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती है, परन्तु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो उस मामले में वह आय केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगा, यदि वह अन्य व्यक्ति उस दूसरे राज्य की सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थित किया गया हो, जिसमें उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं।

### अनुच्छेद - 19

#### पेंशन

1. अनुच्छेद 20 के पैराग्राफ §2§ उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को विगत के नियोजन के लिए अदा की गई पेंशन और इस प्रकार के अन्य पारिश्रमिक केवल उसी राज्य में कर योग्य होंगे।

2. पैराग्राफ §1§ के उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के सामाजिक सुरक्षा विधान के अंतर्गत दी गई पेंशने और अन्य अदायगियां केवल उसी राज्य में कर योग्य होंगी।

### अनुच्छेद - 20

#### सरकारी सेवा

1. §क§ किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उसके उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए, पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में ही कर लग सकेगा।

§ख§ तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं और व्यक्ति उस राज्य का निवासी है, जो :

§i§ उस राज्य का एक राष्ट्रक है: अथवा

§ii§ मात्र सेवाएं पेश करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।

2. §क§ किसी सौविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित कोष द्वारा उसमें से किसी व्यक्ति को उसके द्वारा उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा;
- §ख§ लेकिन, ऐसी पेंशन पर दूसरे सौविदाकारी राज्य में कर केवल तब लग सकेगा यदि व्यक्ति उस अन्य राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।
3. अनुच्छेद 16, 17 और 19 के उपबंध किसी सौविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे ।

### अनुच्छेद - 21

#### अध्यापकों द्वारा प्राप्त किया गया पारिश्रमिक

1. एक प्राध्यापक अथवा अध्यापक जो किसी सौविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तुरन्त पहले दूसरे सौविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा अन्य शैक्षिक संस्था में आग्रम अध्ययन अथवा अनुसंधान अथवा अध्यापन के प्रयोजन के लिए प्रथमोक्तोक्त राज्य में ऐसी अवधि के लिए जो दो वर्षों से अधिक न हो, मौजूद रहता है, द्वारा ऐसे कार्य के लिए प्राप्त किए गए पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि उसके द्वारा ऐसा पारिश्रमिक राज्य से बाहर से प्राप्त किया जाता है ।
2. यदि ऐसा अनुसंधान किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है, तो उस अनुसंधान से प्राप्त आय के संबंध में यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा ।

### अनुच्छेद - 22

#### विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त अदायगियाँ

कोई व्यक्ति जो दूसरे सौविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तुरन्त पहले किसी सौविदाकारी राज्य का निवासी है, मात्र निम्नलिखित कार्य के लिए दूसरे राज्य में अस्थायी रूप से रहता है:

- §क§ उस दूसरे राज्य में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा अन्य ऐसी ही मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था में विद्यार्थी के रूप में; अथवा
- §ख§ एक व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षु के रूप में; अथवा

§ ग § दोनों में से किसी एक राज्य की सरकार से अथवा किसी वैज्ञानिक, शैक्षिक, धार्मिक अथवा सैराती संगठन अथवा किसी भी राज्य की सरकार द्वारा किए गए तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यतया अध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण के लिए कोई अनुदान, भत्ता अथवा पुरस्कार देने वाले के रूप में रहता हो;

उस पर दूसरे राज्य में निम्नलिखित के लिए कर से छूट होगी :

§ क § उसके भरण-पोषण, शिक्षा, अध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए विदेशों से प्रेषित राशियों के लिए;

§ ख § ऐसे अनुदान, भत्ते अथवा पुरस्कार की राशि; और

§ ग § उस दूसरे राज्य में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कोई परिश्रमिक 3000 अमरीकी डालर के बराबर की राशि से अधिक न हो, बशर्ते कि ये सेवाएं उसके अध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण के लिए निष्पादित की गई हों अथवा उसके भरण-पोषण के प्रयोजनों के लिए अनिवार्य हों ।

### अनुच्छेद - 23

#### अन्य आय

1. एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी ।

2. पैराग्राफ § 1 § के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ § 2 § में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक सविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे सविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे सविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति, जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा 15 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे ।

3. पैराग्राफ § 1 § और § 2 § के उपबंधों के होते हुए भी, एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदों पर भी, जिन पर इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे सविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैं, उस दूसरे राज्य में भी कर लगेगा ।

## अध्याय II

## दोहरे कराधान का अपकरण

## अनुच्छेद 24

## दोहरे कराधान का अपकरण

1. दोनों सौंधदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रयुक्त कानून, संबंधित सौंधदाकारी राज्यों में आय के कराधान के मामले में लागू रहेंगे, सिवाय ऐसे मामलों को छोड़कर जहां पर इस करार में उनके विपरीत कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है ।

2. भारत के मामले में, निम्न प्रकार से दोहरे कराधान का अपकरण किया जाएगा:

जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार माल्टा में कर लग सकेगा, वहां भारत, चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा कटौती के द्वारा उस निवासी की आय पर, माल्टा में अंदा की गई आयकर की रकम के बराबर की रकम पर कर से कटौती की अनुमति देगा । तथापि, दोनों मामलों में, ऐसी कटौती की रकम, आयकर {कटौती दिए जाने से पूर्व यथा-संगणित} के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो कि ऐसी आय के कारण हो, जैसी भी स्थिति हो, जिस पर माल्टा में कर लगाया जा सकता है ।

3. पैराग्राफ §2 के प्रयोजनों के लिए "माल्टा में प्रदत्त आयकर" पद में माल्टा कर की वह रकम भी शामिल मानी जाएगी, जिसे माल्टा के कानूनों के अंतर्गत और इस करार के अनुसार माल्टा में स्रोतों से प्राप्त किसी भी आय पर देय होती यदि किसी घटी दर पर आय पर कर न लगाया गया होता अथवा निम्नलिखित के अनुसार माल्टा कर से छूट दी गई होती:-

{क} उद्योग अध्यादेश, 1959 और औद्योगिक विकास अधिनियम, 1988 के लिए सहायना जहां तक वे इस करार के हस्ताक्षर की तारीख को लागू थे, और अब तक संशोधित नहीं किए गए हैं अथवा मामूली तौर पर संशोधित किए गए हैं जिससे कि उनके सामान्य स्वरूप पर प्रभाव न पड़े ; अथवा

{ख} आयकर अधिनियम §अध्याय 123 में किन्हीं अन्य उपबंधों अथवा किसी ऐसे अन्य कानून में जो मौजूदा विशेष प्रोत्साहनकारी कानूनों में संशोधन करके अथवा उनमें परिवर्तन करके बाद में माल्टा में लागू किए जाएं और जब तक कि सौंधदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सारतः उसी स्वरूप के होने पर सहमति प्रकट की जाती हो ।

4. माल्टा के मामले में, दोहरे कराधान का अपकरण निम्न प्रकार से होगा :

विदेशी कर के संबंध में माल्टा कर के प्रति किसी क्रेडिट की छूट के बारे में माल्टा के कानून के उपबंधों के अधीन, जहां इस करार के उपबंधों के अनुसार भारत के भीतर



स्रोतों से प्राप्त आय माल्य कर-निर्धारण में शामिल की जाती है, वहां ऐसी आय पर, उस पर देय संगत माल्य कर के प्रति क्रेडिट के रूप में भारतीय कर की अनुमति दी जाएगी।

5. पैराग्राफ {4} में उल्लिखित कटौती के प्रयोजनों के लिए "ऐसी आय पर भारतीय कर" पद में, भारत के कानूनों के अंतर्गत और इस कटौती के अनुसार, निम्नलिखित के अंतर्गत उस वर्ष के लिए मंजूर की गई कर की किसी छूट अथवा कटौती को छोड़कर ऐसी कोई भी रकम शामिल हुई मानी जाएगी जो किसी भी वर्ष के लिए भारतीय कर के रूप में देय हुई हो:

{क} आयकर अधिनियम, 1961 {1961 का 43} की धारा 10 {4}, 10 {4ख}, 10 {6} {✓ iik}, 10 {15} {✓ i}, 10क, 10ख, 80 1 {क}, 80जजग, 80जजघ, 80जजड, जहां तक कि वे इस कटौती पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख को प्रवृत्त थे और जिन्हें तबसे संशोधित नहीं किया गया है अथवा उनमें केवल छुट-पुट संशोधन किया गया है ताकि उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव न पड़े; अथवा

{ख} कोई अन्य उपबंध जिसे कर-योग्य आय की संगणना में कटौती करने अथवा ऐसी आय को छूट देने अथवा कटौती करने के लिए इसके बाद अधिनियमित किया गया हो जिसके लिए सविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारी भारत के आर्थिक विकास के प्रयोजन के लिए सहमत होते हों, यांवे उसे उसके बाद संशोधित नहीं किया गया है अथवा उसमें केवल छुट-पुट रूप से संशोधन किया गया है ताकि इसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़े।

6. जहां कटौती में यह व्यवस्था हो कि किसी सविदाकारी राज्य में उद्भूत आय से उस राज्य में पूर्णतः अथवा अंशतः कर से छूट दी जाएगी और, दूसरे सविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानून के अंतर्गत उस रकम के संदर्भ द्वारा और न कि उस पूर्ण रकम के संदर्भ द्वारा ऐसी रकम पर कर लग सकता है जिस पर उस दूसरे राज्य में छूट दी जाती है अथवा जो वहां प्राप्त की जाती है तब प्रथमोल्लिखित राज्य में मंजूर की जाने वाली छूट उतनी ही आय पर लागू होगी जितनी कि उस राज्य में छूट दी गई है अथवा प्राप्त हुई हो।

7. ऐसी आय को, जिस पर इस कटौती के उपबंधों के अनुसार किसी सविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जा सकता है, उस सविदाकारी राज्य में लगाए जाने वाले कर की रकम की संगणना के लिए हिसाब में लिया जाए।

## अध्याय V

## विशेष उपबंध

## अनुच्छेद 25

## सम-व्यवहार

1. एक सविदाकारी राज्य के राष्ट्रिक पर दूसरे सविदाकारी राज्य में ऐसे किसी करधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं को लागू नहीं किया जाएगा, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों को वैसी ही परिस्थितियों में लगाए जाने वाले करधान एवं तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न एवं अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हों। यह उपबंध, अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी, उन व्यक्तियों पर लागू होंगे जो एक अथवा दोनों सविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं।

2. एक सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन को, उस दूसरे राज्य में, ऐसा करधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के, वैसी ही परिस्थितियों में अथवा उन्हीं शर्तों के अंतर्गत वैसी ही कार्य में संलग्न उद्यम को लागू होने वाले करधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभों पर, कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है जो कि उस दर से अधिक है जो प्रथमोल्लिखित सविदाकारी राज्य के उसी प्रकार के लाभों पर लगाई जाती है न कि इस कर के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ § 3 के उपबंधों के प्रतिकूल होना है।

3. जिन मामलों में, अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ § 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ § 7 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ § 6 के उपबंध लागू होते हैं, उन्हें छोड़कर, एक सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे सविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया ब्याज, शामिल की गई सेवाओं के लिए रयल्टियाँ और फीस तथा अन्य भुगतान, ऐसे उद्यम के कर लगने योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं समान शर्तों के अधीन कटौती पाने योग्य होंगे जैसे कि वे प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए थे।

4. एक सविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखित सविदाकारी राज्य में कोई ऐसा, करधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उरा करधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो, जो प्रथमोल्लिखित सविदाकारी राज्य में अन्य समान उद्यमों पर समान परिस्थितियों में लागू है अथवा हो सकती है।

5. इस अनुच्छेद की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य ऐसे व्यक्तियों को जो दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी हैं, सिविल स्थिति, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ अथवा किसी अन्य व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण कर के प्रयोजनार्थ किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूटें, राहतें अथवा धट्टियाँ प्रदान करने को बाध्य होगा जो यह अपने निवासियों को प्रदान करता है ।

6. इस अनुच्छेद में "कराधान" पद से वे कर अभिप्रेत हैं जो इस करार के विषय हैं ।

### अनुच्छेद 26

#### परस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार का कर लगाया जा सकता है अथवा लगाया जाएगा जो कि इस करार के उपबंधों के अनुकूल नहीं है तो वह, उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है अथवा, यदि उसका मामला अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ §1§ के अंतर्गत आता है तो वह उस संविदाकारी राज्य को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि यह एक राष्ट्रक है । यह मामला उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुँचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से, जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । किए गए किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रक कानूनों में कोई भी समय-सीमा निर्धारित हो ।

3. इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाइयाँ अथवा शंकाएं उत्पन्न होने पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें परस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में दोहरे कराधान के अपकरण के लिए आपस में परामर्श भी कर सकते हैं जो मागते इस करार में उल्लिखित नहीं हैं ।

4- इस करार को पूर्वोक्त पैराग्राफों के अनुरूप करने के प्रयोजन के लिए सविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। यदि किसी समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से मौखिक बातों का आदान-प्रदान उपयुक्त प्रतीत हो तो ऐसे आदान-प्रदान सविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारियों के प्रतिनिधियों के किसी आयोग के माध्यम से किए जा सकते हैं।

### अनुच्छेद 27

#### सूचना का आदान-प्रदान

1- सविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबंधों अथवा सविदाकारी राज्यों के उन कर्तों से संबंधित आन्तरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं, जो इस करार के अंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन करधान व्यवस्था करार के प्रतिकूल नहीं हो ताकि विशेष रूप से ऐसे कर्तों की घोषा-यद्दी अथवा अपवंचन को रोका जा सके। किसी भी सविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के आन्तरिक कानून के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है। तथापि, यदि सूचना भेजने वाले राज्य में सूचना को मूलतः गुप्त समझा जाता है तो उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा अधिकारियों को जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं प्रकट किया जाएगा जो उन कर्तों का निर्धारण करने अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपराधों का निर्धारण करने से सम्बन्ध हो, जिन पर यह करार लागू होता है। ऐसे व्यक्ति अथवा अधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजन के लिए ही करेंगे परन्तु वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। सक्षम अधिकारी विचार-विमर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित शर्तों, पदतियों और तकनीकों को विकसित करेंगे जिनके बारे में सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा, जिनमें जहां-कहीं उपयुक्त हो, कर अपवंचन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है।

2- किसी भी स्थिति में पैराग्राफ §1 के उपबंधों का अर्थ किसी सविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :-

§क॥ उस अथवा दूसरे सविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपकरण करना;

§ख॥ ऐसी सूचना की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे सविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं है,

§ ग § ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक गुप्त अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो अथवा ऐसी सूचना जिसको प्रकट करना सरकार की नीति § आइरे पब्लिक § के प्रतिकूल है ।

### अनुच्छेद 28

#### राजनयिक तथा कांसुली अधिकारी

1. इस करार की किसी भी बात से राजनयिक एजेन्टों अथवा कांसुली अधिकारियों को अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

### अध्याय 1/1

#### अंतिम उपबंध

### अनुच्छेद 29

#### प्रवर्तन

1. सविदाकारी राज्यों की सरकारें एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगी कि इस करार के प्रवर्तन के लिए सर्वाधिक अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं ।

2. यह करार पैराग्राफ § 1 § में उल्लिखित इन अधिसूचनाओं में से बाद में जारी की गई अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के बाद लागू होगा और इसके उपबंधों का निम्नलिखित प्रभाव होगा :

§ क § भारत में :

जिस कैलेन्डर वर्ष में करार लागू होता है उसके अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी "वित्तीय वर्ष" की आय के संबंध में;

§ ख § माल्टा में :

जिस कैलेन्डर वर्ष में करार लागू होता है उसके अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी "वित्तीय वर्ष" की आय के संबंध में ।

### अनुच्छेद 30

#### समापन

1. यह करार तब तक लागू रहेगा जब तक दोनों में से किसी एक संविदाकारी राज्य द्वारा उसे समाप्त नहीं कर दिया जाता है। दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार को लागू होने से पांच वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद आरम्भ होने वाले किसी कैलेंडर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छः मास पूर्व, राजनयिक माध्यमों से इसकी समाप्ति का नोटिस देकर इस करार को समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह करार निम्नलिखित के लिए निष्प्रभावी हो जाएगा :

§क§ भारत में :

जिस कैलेंडर वर्ष में करार के समापन की सूचना दी जाती है इसके अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के पहले दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी "वित्तीय वर्ष" की आय के संबंध में ;

§ख§ माल्टा में :

जिस कैलेंडर वर्ष में करार के समापन की सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी "वित्तीय वर्ष" की आय के संबंध में ।

जिसके समर्थ में, इसके लिए विधिवत रूप से संबंधित दोनों सरकारों द्वारा प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

बलेटा, माल्टा ने वर्ष एक हजार गी सी बीरानेवे के सितम्बर माह के 28वें दिन हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में दो प्रतियों में निम्नलिखित किया गया। दोनों पाठ सामान्य रूप से प्रामाणिक हैं। दोनों पाठों के बीच भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की  
सरकार की ओर से

माल्टा सरकार  
की ओर से

मालाबल्ली वेन्कटप्पा,

जान हत्सी,

कन्वेंशनर मूर्ध्नि,

वित्त मंत्री

केन्द्रीय मंत्री (राज्य) वित्त

राजस्व एवं व्यय

[ अधिसूचना सं. 9908 वि. 22-11-95/सं. सं. 503/1/89-एफ.टी.-डी. ]

बी. बी. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
(Department of Revenue)  
(Foreign Tax Division)

**NOTIFICATION**

**INCOME-TAX**

**G.S.R. 761(E).—Whereas** the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Republic of Malta for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has entered into force on 8th February, 1995, after the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required under their laws for bringing into force of the said Agreement in accordance with paragraph 1 of the Article 29 of the said Agreement :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

"Annexure"

**AGREEMENT BETWEEN  
THE REPUBLIC OF INDIA  
AND  
MALTA  
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION  
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION  
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME**

**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF MALTA**

**Desiring to conclude an Agreement for the avoidance  
of double taxation and the prevention of fiscal evasion with  
respect to taxes on income,**

**HAVE AGREED AS FOLLOWS:**



## CHAPTER I

## SCOPE OF THE AGREEMENT

## Article 1

## Personal Scope

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

## Article 2

## Taxes Covered

(1) The existing taxes to which this Agreement shall apply are:

(a) in India:

the income tax including any surcharge thereon;

(hereinafter referred to as "Indian tax");

(b) in Malta:

the income tax;

(hereinafter referred to as "Malta tax").

(2) This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph (1). The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which are made in their respective taxation laws.

(3) Notwithstanding the other provisions of this Article, this Agreement shall not apply to tax paid or payable in Malta in accordance with the provisions of subsection (11) of section 31 of the Income Tax Act (Cap.123), concerning the chargeable income of any person engaged in the production of petroleum produced in Malta, or any substantially similar provision which is imposed after

the date of signature of this Agreement.

## CHAPTER II

### DEFINITIONS

#### Article 3

##### General Definitions

- (1) For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
- (a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with international law/the U.N. Convention on the Law of the Sea;
  - (b) the term "Malta" when used in a geographical sense, means the Island of Malta, the Island of Gozo and the other islands of the Maltese archipelago including the territorial waters thereof, and any area outside the territorial sea of Malta which, in accordance with international law, has been or may hereafter be designated, under the law of Malta concerning the Continental Shelf, as an area within when the rights of Malta with respect to the seabed and subsoil and their natural resources may be exercised;
  - (c) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
  - (d) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative; and in the case of Malta, the Minister responsible for finance or his authorised representative;
  - (e) the term "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Malta as the context requires;

- (f) the term "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (g) the term "fiscal year" in relation to Indian tax means "previous year" as defined in the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) and in relation to Malta tax means the year immediately preceding the "year of assessment" as defined in the Income Tax Act (Cap.123);
- (h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (i) the term "national" means any individual possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in the Contracting State;
- (j) the term "person" includes an individual a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (k) the term "tax" means Indian tax or Malta tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes.
- (2) As regards the application of the Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which this Agreement applies.

## Article 4

### Resident

(1) For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

(2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has no permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of paragraph (1) of a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

## Article 5

### Permanent Establishment

(1) For the purposes of this Agreement the term "Permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

(2) The term "permanent establishment" includes especially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, quarry or any other place of extraction of natural resources including an offshore drilling site;
- (g) a building site or construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activities (together with other such sites, projects or activities, if any) continues for a period of more than six months;

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise any other activity of a preparatory or auxiliary character.

(4) A person engaged in a Contracting State in exploration of the seabed and its sub-soil or in exploitation of natural resources situated there as well as in activities which are complementary or auxiliary to such activities, is deemed to exercise such activities through a permanent establishment in that State.

(5) An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if:

(a) substantial equipment is in that other State being used or installed by, for or under contract with the enterprise;

(b) it carries on supervisory activities in that State in connection with the use of equipment referred to in sub-paragraph (a).

(6) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2) where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph (7) applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

(7) An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of the enterprise, he shall not be considered as agent of an independent status if the transactions between the agent and the enterprise were not made under arm's length conditions.

(8) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

### CHAPTER III

#### TAXATION OF INCOME

##### Article 6

##### Income from Immovable Property

(1) Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work or to explore for, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

(3) The provisions of paragraph (1) shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

## Article 7

### Business Profits

(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanent establishment. The words "directly or indirectly" mean, for the purposes of this Article, that where a permanent establishment takes an active part in negotiating, concluding or fulfilling contracts entered into by the enterprise, then, notwithstanding that other part of the enterprise have also participated in those transactions, there shall be attributed to the permanent establishment that proportion of profits of the enterprise arising out of those contracts as the contribution of the permanent establishment to those transactions bears to that of the enterprise as a whole.

(2) Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment or with other associated enterprises with which it deals.

(3) In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses of the enterprise, being expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment (including executive and general administrative expenses so incurred) and which would be deductible if the permanent establishment were an independent entity which paid those expenses, whether incurred in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere in accordance with the provisions of and subject to the limitation of the taxation laws of that State.



(4) Nothing in this Article shall affect the application of any law of a Contracting State relating to the determination of the tax liability of a person, including the determination of such liability by the exercise of discretion or the making of an estimate by the competent authority of that State in cases in which, from the information available to the competent authority of that State, it is not possible or not practicable to ascertain the profits to be attributed to a permanent establishment, provided that law shall be applied, so far as the information available to the competent authority permits, consistently with the principles of this Article.

(5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

(6) For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

(7) The provisions of this Article shall not affect the provisions of the law of a Contracting State regarding the taxation of profits from the business of insurance.

(8) Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

## Article 8

### Shipping and Air Transport

(1) Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation by that enterprise of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

(2) For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall mean profits derived by an enterprise described in paragraph 1 from the transportation by sea or air respectively of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of ships or aircraft including:

- (a) the sale of tickets for, such transportation on behalf of other enterprises;
  - (b) other activity directly connected with such transportation; and
  - (c) the rental of ships or aircraft incidental to any activity directly connected with such transportation.
- (3) Profits of an enterprise of a Contracting State described in paragraph (1) from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers, barges and related equipment for the transport of containers) used in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
- (4) The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to profits from participation in a pool, a joint business, or an international operating agency.
- (5) For the purposes of this Article interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft, and the provisions of Article 11 (Interest) shall not apply in relation to such interest.

## Article 9

### Associated Enterprises

- (1) Where:
- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
  - (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial

relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

(2) Nothing in this Article shall affect the application of any law of a Contracting State relating to the determination of such liability by the exercise of a discretion or the making of an estimate by the competent authority of that State in cases which, from the information available to the competent authority of that State, it is not possible or not practicable to determine the income to be attributed to an enterprise, provided that law shall be applied, so far as the information available to the competent authority permits, consistently with the principles of this Article.

(3) Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State, and taxes accordingly, profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to that enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

## Article 10

### Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but:

(a) where the dividends are paid by a company resident of India to a resident of Malta who is the beneficial owner thereof, the Indian tax so

charged shall not exceed:

- (i) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least 25 per cent of the shares of the company paying the dividends; and
  - (ii) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
- (b) where the dividends are paid by a company which is a resident of Malta to a resident of India who is the beneficial owner thereof Malta tax on the gross amount of the dividends shall not exceed that chargeable on the profits out of which the dividends are paid.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

(3) The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or

insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly or profits or income arising in such other State.

## Article 11

### Interest

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (2), interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if it is derived by the Government of the other Contracting State or a local authority thereof or any agency or instrumentality wholly owned and controlled by that government or local authority.

(4) The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.

(5) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(7) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them, and some other person, the amount of the interest having regard to the debt claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

## Article 12

### Royalties and Fees for Included Services

(1) Royalties and fees for included services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such royalties and fees for included services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for included services the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties or fees for included services.

(3) The term "royalties" in this Article means payments or credits, whether periodical or not, and however described or computed, to the extent to which they are made as consideration for:

- (a) the use of, or the right to use any copyright, patent, design or model, plan, secret formula or process, trademark or other like property or right;

- (b) the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment;
  - (c) the supply of scientific, technical, industrial or commercial knowledge or information;
  - (d) the use of, or the right to use:
    - (i) motion picture films;
    - (ii) films or video tapes for use in connection with television; or
    - (iii) tapes for use in connection with radio broadcasting; or
  - (e) total or partial forbearance in respect of the use or supply of any property or right referred to in this paragraph.
- (4) The term "fees for included services" in this Article means payments or credits, whether periodical or not, and however described or computed, to the extent to which they are made as consideration for:
- (a) the supply of any assistance that is ancillary and subsidiary to, and is furnished as a means of enabling the application or enjoyment of, any such property or right as is mentioned in sub-paragraph (a) of paragraph (3), or any such equipment as is mentioned in sub-paragraph (b) of paragraph (3), or any such knowledge or information as is mentioned in sub-paragraph (c) of paragraph (3);
  - (b) rendering of any technical or consultancy services (including the provision of technical or other personnel) if such services make available technical knowledge, (experience, skill, know-how or process or consist of the development and transfer of a technical plan or technical design.
- (5) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for included services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for included services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from fixed base situated therein, and the right or property

in respect of which the royalties or fees for included services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

(6) Royalties and fees for included services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for included services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for included services was incurred, and such royalties or fees for included services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise, in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(7) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for included services having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

### Article 13

#### Technical Fees

(1) Technical fees arising in a Contracting State which are derived by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such technical fees may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State; but if the recipient is the beneficial owner of the technical fees, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the technical fees.

(3) The term "technical fees" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than to an



employee of the person making the payments, in consideration for any services of a technical, managerial or consultancy nature.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the technical fees, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the technical fees arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services, and the technical fees are effectively connected with such permanent establishment or such services. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

(5) Technical fees shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a statutory body thereof, or a resident of that State. Where, however, the person paying the technical fees, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the obligation to pay the technical fees was incurred, and such technical fees are borne by that permanent establishment, then such technical fees shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

(6) Where, by reason of a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the technical fees paid exceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State due regard being had to the other provisions of this Agreement.

#### Article 14

##### Alienation of Property

(1) Income from gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph (2) of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

(2) Income from gains from the alienation of shares

or comparable interests in a company, the assets of which consist wholly or principally of immovable property, may be taxed in the Contracting State in which the assets or the principal assets of the company are situated.

(3) Income from gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such income or gains arising from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in the other State.

(4) Income from gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

(5) Income from gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph (2) in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

(6) Income from gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs (1), (2), (3), (4) and (5) shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

## Article 15

### Independent Personal Services

(1) Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State. However, such income may be taxed in the other Contracting State in the following circumstances:

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities in which case only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or

(b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 90 days during any fiscal year.

(2) The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

## Article 16

### Dependent Personal Services

(1) Subject to the provisions of Articles 17, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed only in that State.

## Article 17

## Directors' Fees

Directors' fees and similar payments derived by a resident of one of the Contracting States in his capacity as a member of the board of directors, or other comparable body however described, of a company which is a resident of the other Contracting State, may be taxed in that other State.

## Article 18

## Income Earned by Artistes &amp; Athletes

(1) Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artiste or a musician or as an athlete from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other Contracting State.

(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income, may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political subdivisions or local authorities.

(4) Notwithstanding the provisions of paragraph (2) and Articles 7, 15 and 16, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State, if that other person is supported

wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political subdivisions or local authorities.

## Article 19

### Pensions

(1) Subject to the provisions of paragraph (2) of Article 20, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), pensions and other payments made under the social security legislation of a Contracting State shall be taxable only in that State.

## Article 20

### Government Service

(1) (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purposes of rendering the services.

(2) (a) Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only

in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

(3) The provisions of Articles 16, 17 and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with any business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

#### Article 21

##### Remuneration received by Teachers

(1) Remuneration which a professor or teacher who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State for a period not exceeding two years for the purpose of carrying out advanced study or research or for teaching at a university, college, school or other educational institution receives for such work shall not be taxed in that State, provided that such remuneration is derived by him from outside that State.

(2) This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

#### Article 22

##### Payments received by Students and Trainees

An individual who is a resident of a Contracting State immediately before making a visit to the other Contracting State and is temporarily present in the other State solely:

- (a) As a student at a recognised university, college, school or other similar recognised educational institution in that other State; or
- (b) as a business or technical apprentice; or
- (c) as a recipient of a grant, allowance or award for the primary purpose of study, research or training from the government of either State or from a scientific, educational, religious, or charitable organisation or under a technical assistance programme entered into by the

Government of either State,

shall be exempt from tax in that other State on:

- (a) all remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education, study, research or training;
- (b) the amount of such grant, allowance or award; and
- (c) any remuneration not exceeding an amount equivalent to US \$ 3,000 during any fiscal year in respect of services in that other State provided the services are performed in connection with his study, research or training or are necessary for the purpose of his maintenance.

### Article 23

#### Other Income

(1) Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph (2) of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2) items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing articles of this Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

## CHAPTER IV

## ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

## Article 24

## Elimination of Double Taxation

(1) The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where express provision to the contrary is made in this Agreement.

(2) In the case of India double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Malta, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Malta whether directly or by deduction. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax (as computed before the deduction is given) which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in Malta.

(3) For the purposes of paragraph (2), the term "income tax paid in Malta" shall be deemed to include the amount of Malta tax which would, under the laws of Malta and in accordance with this Agreement, have been payable on any income derived from sources in Malta had the income not been taxed at a reduced rate or exempted from Malta tax in accordance with:

- (a) the Aids to Industries Ordinance, 1959 and the Industrial Development Act, 1988 in so far as they were in force on, and have not been modified since, the date of signature of this Agreement or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character; or
- (b) any other provisions in the Income Tax Act (Cap.123) or in any other legislation which may subsequently be introduced in Malta in modification of, or in addition to, the existing special incentive laws so far as they are agreed by the competent authorities of the Contracting States to be of a substantially similar



character.

(4) In the case of Malta, double taxation shall be eliminated as follows:

Subject to the provisions of the law of Malta regarding the allowance of a credit against Malta tax in respect of foreign tax, where, in accordance with the provisions of this Agreement, there is included in a Malta assessment income from sources within India the Indian tax on such income shall be allowed as a credit against the relative Malta tax payable thereon.

(5) For the purposes of the deduction referred to in paragraph (4), the term "Indian tax on such income" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax under the laws of India and in accordance with this Agreement for any year but for an exemption from, or reduction of, tax granted for that year under:

(a) Section 10(4), 10(4B), 10(6)(vii), 10(15)(iv), 10A, 10B, 80IA, 80HHC, 80HHD, 80HHE of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), so far as they were in force on, and have not been modified since, the date of the signature of this Agreement, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character; or

(b) any other provisions which may be enacted hereafter granting a deduction in computing the taxable income or an exemption or reduction from tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purposes of the economic development of India, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.

(6) Where the Agreement provides that income arising in a Contracting State shall be relieved from tax in that State, either in full or in part, and, under the law in force in the other Contracting State, such income is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in that other State and not by reference to the full amount thereof, then the relief to be allowed in the first mentioned State shall apply only to

so much of the income as is remitted to or received in the other State.

(7) Income which, in accordance with the provisions of this Agreement, is not to be subjected to tax in a Contracting State, may be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State.

## CHAPTER V

### SPECIAL PROVISIONS

#### Article 25

##### Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

(2) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which an enterprise of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar enterprise of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph (3) of Article 7 of this Agreement.

(3) Except where the provisions of paragraph (1) of Article 9, paragraph (7) of Article 11, or paragraph (6) of Article 12 apply, interest, royalties and fees for included services and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be

deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first mentioned State.

(4) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirements connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances.

(5) Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to individuals who are resident of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes on account of civil status, family responsibilities or any other personal circumstances which it grants to its own residents.

(6) In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

## Article 26

### Mutual Agreement Procedure

(1) Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the

### Contracting States.

(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

### Article 27

#### Exchange of Information

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject ~~of the Agreement~~ of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

(2) In no case shall provisions of paragraph (1) be construed so as to impose on a Contracting State the

obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

#### Article 28

##### Diplomatic and Consular Officials

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

#### CHAPTER VI

##### FINAL PROVISIONS

#### Article 29

##### Entry into Force

(1) The Governments of the Contracting States shall notify each other that the legal requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with.

(2) The Agreement shall enter into force thirty days after the date of the later of the notifications referred to in paragraph (1) and its provisions shall have effect:

(a) in India:

as regards income for any "fiscal year" beginning on or after the first day of April of the calendar year next following that in which this Agreement enters into force;

(b) in Malta:

as regards income for any "fiscal year" beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Agreement enters into force.

### Article 30

#### Termination

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

(a) in India:

as regards income for any "fiscal year" beginning on or after the first day of April of the calendar year next following that in which the notice of termination is given;

(b) in Malta:

as regards income for any "fiscal year" beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the notice of termination is given.

In witness whereof the aforesaid, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Vaelta, Malta this twenty eighth day of September, 1994, in duplicate in the English and Hindi languages, both texts being equally authentic. In case of divergence between the two texts the English text shall be the operative one.

For the Government of  
the Republic of India

For the Government of  
Malta

MALAVALLI VENKATAPPA  
CHANDRASHEKARA MURTHY,  
Minister of State for  
Revenue and Expenditure

JOHN DALLI,  
Minister of Finance

[Notification No. 9908 dated 22-11-95/F. No. 503/1/89/FTD.]

V. B.\* SRINIVASAN, Jt. Secy.

